मिनिस्ट्री से पूछें, जो इस सबजेक्ट को डील करते हैं और जिसके मातहत ये फैक्टरियां काम कर रही हैं।

SHRI BAL RAJ MADHOK: According to the statement laid on the Table, total imports of fertilisers for this year and the next are going to be of the value of about $ 300 million, that is, more than Rs. 200 crores. In view of the fact that we have plenty of raw materials for manufacture of fertilisers in the country and that in Sindri we have developed the technical know-how and we have also a project in Ranchi to manufacture plants, can we not stop these imports or at least reduce them and concentrate our energy and money on establishing indigenous fertiliser factories so that so much of waste and so much of foreign exchange could be saved ?

SHRI IQBAL SINGH : That is also a matter of argument. The need is of today. Whether we import, say, 10 maunds of foodgrains of fertiliser to produce these 10 maunds in the country is the choice before the country. We have to make that choice because the demand is for today. So we have to import for today.

SHRI KIRUTTINAN: Is it a fact that the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission in its report on fertilisers and manure in agricultural production has suggested the need for fixation of targets and distribution of fertilisers on a scientific basis ? If so, what are the other suggestions made by the Organisation, and what steps have been taken to implement them ?

SHRI IQBAL SINGH: I am not aware of any such report.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the hon. Minister tell us (1) what is the method we adopt to purchase fertilisers from abroad ? Is it by tender ? (2) What is the method adopted to ensure quality control ? and (3) Do Government negotiate with the co-operative fertilisers' unit in America to take advantage of the reduced purchase price ?

SHRI IQBAL SINGH: Except that which we purchase under AID, except that from USA and Canada, all our purchases are by negotiation. We purchase from the open market. Wherever it is available cheap, we go there, according to time, the availability of resources and our need also. We co-ordinate our whole programme and we have been successful. We have made the cheapest purchase.

SHRI JYOTIRMOY BASU: My question was whether they invite global tender, what method they adopt to ensure the quality at the point of shipment, because most of it is sub-standard.....

SHRI IQBAL SINGH: We ensure quality control at the time of shipment.

SHRI JYOTIRMOY BASU: How ?

SHRI IQBAL SINGH: Through the Supply Mission.

विकसित देशों से पूंजी

+

*392. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामजी राम :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिसमें उन्होंने विकसित देशों से पूंजी के शांतिपूर्ण और योजनाबद्ध स्थानान्तरण की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस नीति को अपनाने के लिए अन्य देशों में अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): सरकार ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाने के लिए, विकसित देशों से विकासशील देशों में पूंजी के साधनों को शान्तिपूर्ण और योजनाबद्ध ढंग से लाने की बड़ी जरूरत है। सरकार ने इस नीति का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र

संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार और विकास सम्मेलन जैसे संगठनों में भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1960 में एक संकल्प पास किया था जिसमें यह आशा प्रकट की गयी थी कि दी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और पूंजी में काफी वृद्धि की जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके, यह आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों की मिली जुली राष्ट्रीय आमदनी के लगभग एक प्रतिशत के बराबर हो सके। इस संकल्प में व्यक्त की गयी आशा, अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन, यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जा रही है कि विकसित देशों की पूंजी का शांतिपूर्ण तथा योजनाबद्ध ढंग से आना जरूरी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है, यह संकल्प 1960 में पारित हुआ था और विकसित देशों ने सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार भी किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उन देशों से यह जानकारी लेने का यत्न किया है कि कौन सी कठिनाइयां उनके मार्ग में बाधक हैं, जिनके कारण इस संकल्प को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका।

श्री मोरारजी देसाई : व्यक्ति और समाज अच्छे संकल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मगर उनमें अमल करने में हमेशा ढिलाई होती है। इस बारे में सरकार कुछ भी करे, इस संकल्प पर उनसे अमल करवाना उतना आसान नहीं है, मगर आशा है कि अब जबकि ज्ञान हुआ है और समझ आई है, तो अमल भी होने लगेगा। कुछ तो अमल होता रहता है, मगर पूरा अमल नहीं हुआ है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विकसित देशों में कौन से देश इस प्रकार के हैं, जो इस संकल्प को तत्काल अथवा अंशतः कार्यान्वित करने के लिए तैयार हो गए हैं।

श्री मोरारजी देसाई : सब इसके लिए तैयार हुए हैं और सब कुछ न कुछ तो दे ही रहे हैं। तीन चार सालों में इस बारे में कुछ कमी हुई है। उसमें सम्बद्ध देशों की परिस्थिति और राजनीतिक स्थिति आदि सारी बातें बीच में आती हैं। मगर ऐसी आशा है कि इस बारे में कुछ प्रगति होगी।

श्री शिव कुमार शास्त्री : अगर सरकार की वांछित नीति पर आचरण किया जाये और विकसित देश सहायता दें, तो भारत की वर्तमान मुद्रा स्थिति पर उसका क्या प्रभाव होगा।

श्री मोरारजी देसाई : हमारी स्थिति आसान हो जायेगी।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : विदेशों से मिलने वाली सहायता के बावजूद हमारी योजनाएं ठीक ढंग से सफल नहीं हो रही हैं और देश पर कर्ज का भार भी बढ़ता जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस के इलाज के रूप में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री मोरारजी देसाई : यह बात सही नहीं है कि हमारी योजनायें सफल नहीं हो रही हैं और इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हां, अगर यह बात कही जाये कि हमारी योजनाएं पूरी सफल नहीं हुई हैं, यानी उनमें कुछ न कुछ कमी रही है, तो उसके साथ मेरा झगड़ा नहीं है। जहां तक कर्ज का भार बढ़ने का प्रश्न है, अगर हमने ज्यादा विकास करना है और ज्यादा आगे बढ़ना है, तो पहले तो कर्ज बढ़ेगा ही, मगर जो विकास होगा, उस में से वह कर्ज चुकाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की जो यह नीति इस संबंध में है और जहां तक मेरी सूचना है दुनिया के सारे विकासशील देश जो हैं वह इस नीति के साथ सहमत हैं, सभी यह चाहते हैं कि जो विकसित देश हैं वह अपनी पूरी पूंजी का एक प्रतिशत इन विकासशील

देशों के उत्थान के लिए लगाएं लेकिन पिछले सात-आठ वर्षों से यह प्रयास और प्रस्ताव होने के बावजूद भी इस में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है तो अगर सामूहिक रूप से सभी देश इस में सहमत नहीं हैं तो अलग-अलग कुछ देशों से जो इस संबंध में विशेष सहायता कर सकते हैं उन के साथ बात करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : दोनों बातें चल रही हैं। मगर जब तक देने वाला तैयार न हो तो तब तक लेने वाला उस के ऊपर यह जबर्दस्ती कैसे करे ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दुनिया के दारिद्रय को निपटाने से संबंध रखता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में यह साम्राज्यवादी शोषण जो चल रहा है कि कच्चा माल हम यहां से भेजते हैं और उस के बदले में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डेवलप्ड कन्ट्रीज से आते हैं, इस में विदेशी सहायता जो मिलती है वह कितने प्रतिशत है और यह जो इनका अनुपात है उस को मिटाने के लिए मन्त्री महोदय क्या सोच रहे हैं। जो हमारे देश से कच्चा माल जाता है जिससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वह भेजते हैं और इसमें जो शोषण करते हैं उस का यह जो विदेशी कर्जा है वह कितने प्रतिशत है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह प्रतिशत तो हरएक देश का अलग-अलग हो सकता है। उसकी अभी तो मेरे पास तफसील नहीं है। चाहें तो मैं बाद में दे सकता हूं। मगर वह हमारा शोषण इस तरीके से कर रहे हैं यह कहना ठीक नहीं होगा। हम अपनी खुशी से सामान बेचते हैं और अपनी खुशी से लेते हैं।

SHRI LOBO PRABHU: I would like to know from the hon. Minister if he has appreciated that there is surplus machine-building capacity in foreign countries, that these countries are more anxious to find market than we are to find plants and import them and that the terms of trade have changed if so, in these circumstances, will the Minister make it clear that we are not going to take tied aid and we are not otherwise going to prevent foreign investment coming into the country in order to relieve the over-production of machine-building capacity in other countries.

SHRI MORARJI DESAI: I hope the hon. Member does not feel that if tied aid only comes we should not take it at all. I think that would be a suicidal decision.

SHRI LOBO PRABHU: Sir, tied aid was only a part of my question. I want a more detailed reply to my question, whether they are prepared to change the strategy where instead of begging we wait for those people to come to us.

SHRI MORARJI DESAI: Sir, I refute the idea that we are going about begging. There is no question of any begging at all. If the hon. Member to have that in mind how can I help him. I hope this Government and this country will not be charged with this kind of an attitude. That does not redound to anybody's credit. It is not only that we are not doing it, if we negotiate we negotiate on equal terms with self-respect. If it does not come, it does not come; if it comes, it comes. If the hon. Member thinks it is open to us to negotiate and get what he wants, he is very much mistaken.

श्री तुलशीदास जाधव : जो विकसित देश हैं उन से मदद या लोन हम चाहते हैं वह उतना मिलता है क्या और नहीं मिलता तो क्या उस का ऐसा कोई कारण है कि जो मुल्क देते हैं उस का रिटर्न या आउटपुट ठीक रीति से नहीं होता इसलिए वह नहीं देते, ऐसा कुछ कारण है क्या ?

श्री मोरारजी देसाई : जो कारण सम्मानित सदस्य समझते हैं वह कारण नहीं है।

SHRI HEM BARUA: In spite of a series of discussions and the romances of some delegates with some Indian girls the UNCTAD meeting in session currently in Delhi, it is reported, has not succeeded in narrowing the gap between the developed countries an

the developing countries. If that is so, may I know whether our Government has taken up the matter so as to narrow down the gap between developed and developing countries and whether this lack of narrowing the gap between the developed and developing countries is going to affect India so far as finance is concerned?

SHRI MORARJI DESAI: The hon. Member may be interested in knowing about romances. I am not. Therefore, I know nothing about it and I cannot reply to that. As far as the narrowing down of the gap is concerned, it is true that it is not taking place and that is why discussions are going on. If it had been a very simple matter, it would have been achieved immediately. It is not such a simple matter. It takes time for both sides to come to conclusions but I think ultimately good results will flow out of such discussions.

SHRI HEM BARUA: Part (b) of my question has not been answered. Is this lack of narrowing down going to affect adversely the financial assistance coming from the developed countries to India?

SHRI MORARJI DESAI: It is possible that this will lesson the finances coming to this country. But it will not always be the case. It will also help to spur us to make our efforts.

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष जी, विकसित देशों का जो संकल्प एक प्रतिशत आमदनी में हमें सहायता देने का है, उन के संकल्प के अनुसार हमें एक प्रतिशत के आधार पर सहायता नहीं मिलती, तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह विकसित देशों में कौन सा देश है जो अपने संकल्प की पूर्ति में हिचकिचाहट दिखा रहा है।

श्री मोरारजी देसाई : देशों का इस तरह से मुकाबला करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता।

SHRI S. S. KOTHARI: There is a marked shift in the attitude of the United States and Western countries in regard to maintaining the levels of foreign aid at precious levels. In view of the possibility of decline in such development aid, may I know how it would effect our maintenance imports and the projects which we have on hand?

SHRI MORARJI DESAI: Maintenance imports may be affected if the amount of aid is not coming to the required extent and, in that sense, there will be difficulties. But those difficulties will also show us the remedies how to make us forego those imports.

PLAN OUTLAY FOR 1968-69

+

*393. SHRI CHINTAMANI PANIGARHI:
SHRI K. M. ABRAHAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total outlay of annual Plan of each State approved by the Planning Commission for the year 1968-69;

(b) the amount of Central assistance extended to each State for the same period; and

(c) the reasons for the cut, if any, in the outlay of the annual Plan of each State for the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): (a) Outlay for the Annual Plans of the States for 1968-69 have not yet been finalised.

(b) A statement is laid on the Table of the House indicating the distribution of Rs. 590 crores out of a total Central assistance of Rs. 615 crores. [*Placed in Library. See.* No. LT-300 /68]. Allocation of the balance of Rs. 25 crores has not yet been made.

(c) The question does not arise.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Out of this Central assistance of Rs. 615 crores, the States by way of payment of interest to the Central Government on the loans incurred all these years are paying nearly Rs. 400 crores. I hope my figure is correct. In view of this burden on the State Governments by way of payment of interest and return of capital of nearly Rs. 400 crores to the Central Government when they are getting only Rs. 615 crores by way of Central assistance, may I know whether the government is going to review and rationalise the payment of interest and repayment of loans by the States by giving fresh thought to this problem so that the States may not be over-burdened.

SHRI K. C. PANT: Out of Rs. 615 crores, as I said, Rs. 25 crores have been